

ग्रामीण खाद्य सुरक्षा पर शहरीकरण के प्रभाव का अध्ययन

SHOURYA PRATAP SINGH

Research Scholar, Sunrise University, Alwar Rajasthan

DR. OM PRAKASH SHARMA

Research Supervisor, Sunrise University, Alwar Rajasthan

सारांश

विकसित और विकासशील दोनों देशों में शहरीकरण बढ़ रहा है। 1950 में, दुनिया की 30 प्रतिशत आबादी शहरी इलाकों में रहती थी, जो 2002 तक बढ़कर वैश्विक आबादी का 47 प्रतिशत हो गई (संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग, 2002)। औद्योगिक देशों की तीन चौथाई से अधिक आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है, जबकि विकासशील देशों में ग्रामीण से शहरी प्रवास तेजी से बढ़ रहा है। यह तीव्र शहरीकरण ऐतिहासिक मानकों द्वारा अभूतपूर्व है। फिर भी, शहरीकरण दर विकासशील क्षेत्रों में व्यापक रूप से भिन्न है; जबकि लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में 78 प्रतिशत शहरीकरण है, अफ्रीकी में 34 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। 2020 तक दुनिया की लगभग आधी आबादी (46.2 प्रतिशत) शहरीकृत हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) ने परिभाषित किया है कि खाद्य सुरक्षा एक ऐसी स्थिति है जब सभी लोग सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए अपनी आहार संबंधी जरूरतों और खाद्य प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक भौतिक और आर्थिक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। इस परिभाषा में मुख्य रूप से घरेलू खाद्य सुरक्षा के चार प्रमुख आयाम शामिल हैं: उपलब्धता, स्थिरता, सुरक्षा और पहुंच। शहरी वातावरण के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा के चार प्रमुख पहलुओं में से प्रत्येक की व्याख्या की जा सकती है। पहला आयाम (खाद्य उपलब्धता) सामान्य उपलब्धता या पर्याप्त मात्रा में भोजन के स्टॉक से संबंधित है। यह मुख्य रूप से खाद्य उत्पादन और आपूर्ति की भूमिका है। उत्पादन और आपूर्ति दोनों प्रणालियों में ग्रामीण और शहरी संदर्भों में अंतर है।

मुख्यशब्द:- ग्रामीण खाद्य सुरक्षा, शहरीकरण के प्रभाव, ग्रामीण और शहरीक्षेत्र

प्रस्तावना



खाद्य स्थिरता के लिए आवश्यक है कि भोजन को किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। खाद्य सुरक्षा भोजन की गुणवत्ता या पौष्टिकता से जुड़ी है। यह पर्याप्त नहीं है कि पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध हो , यदि बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम उठाए बिना इसका सेवन नहीं किया जा सकता है। कई अध्ययनों में पाया गया कि शहरीकरण आम तौर पर बाल कुपोषण को कम करता है और आहार विविधता को बढ़ाता है (रूएल और गैरेट 2004)। हालांकि , कई विकासशील देशों में स्ट्रीट फूड स्टॉल अबाधित हैं। स्टालों को अक्सर पर्याप्त प्रशीतन, पानी और स्वच्छता सुविधाओं की आवश्यकता होती है। विक्रेता अक्सर भोजन को सुरक्षित रूप से तैयार करने , संभालने और भंडारण करने में कुशल नहीं होते हैं। इसलिए , विकासशील देशों (मैक्सवेल एट अल , 2000; एफएओ 2002) में स्ट्रीट फूड और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संक्रमण की घटना के बीच सीधा संबंध देखा गया है।

विश्व स्तर पर, ये संक्रमण विशेष रूप से बच्चों में मृत्यु दर का एक प्रमुख कारण हैं। भोजन तक पहुंच का मुख्य पहलू उन संसाधनों से संबंधित है जो एक व्यक्ति या परिवार के पास स्वस्थ आहार के लिए आवश्यक भोजन प्राप्त करने के लिए है। इस प्रकार , शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए , भोजन की पहुंच मुख्य रूप से भोजन खरीदने की घरेलू क्षमता पर संकेत देती है। अधिकांश शहरी गरीबों के पास बड़े खाद्य भंडार नहीं होते हैं, न ही उनके पास स्वयं के खाद्य उत्पादन के लिए क्षेत्रों तक पहुंच होती है। शहरी झुग्गी , अक्सर धनी शहरी समकक्षों की तुलना में भोजन की खरीद के लिए अतिरिक्त भुगतान करते हैं , क्योंकि वे रोजाना कम मात्रा में भोजन खरीदने के आदी होते हैं क्योंकि उनके पास संसाधन या रहने की स्थिति नहीं होती है जो उन्हें घर पर बड़ी मात्रा में भोजन खरीदने और संग्रहीत करने की अनुमति देती है।

ग्रामीण परिदृश्य का शहरीकरण

20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में , उद्योग, बुनियादी ढांचे और परिवहन के बढ़ते विकास और कृषि के आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए , जिससे नई जनसांख्यिकीय प्रक्रियाओं का उदय हुआ , आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन हुआ , भूमि उपयोग, निर्माण और संरचना और बस्तियों का कार्य। ग्रामीण क्षेत्रों को कृषि पहलू से परे देखा जाता है , क्योंकि शहरी-ग्रामीण प्रवासियों की वृद्धि और नए कार्यों के उद्भव के साथ , वे तेजी से शहर की बस्तियों के समान हो जाते हैं। औद्योगिकीकरण ,



शहरीकरण और शहर के ध्रुवीकरण के प्रभाव ने ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषिकरण , गैर-ग्रामीणीकरण और आबादी को कम करने की स्पष्ट प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित किया।

शहरीकरण को इस वर्तमान शताब्दी के प्रमुख रुझानों में से एक के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है, और यह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों (यूएनएफपीए , 2007) में गरीबी में कमी के लिए महत्वपूर्ण अवसरों के साथ-साथ महत्वपूर्ण चुनौतियों की पेशकश करता है। जनसांख्यिकीय दृष्टि से , शहरीकरण शहरी के रूप में निर्दिष्ट क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के हिस्से को संदर्भित करता है। 2009 के बाद से दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी ऐसी बस्तियों में रहती है। 2009 और 2050 के बीच , शहरी क्षेत्रों में पूरी दुनिया की जनसंख्या वृद्धि को आकर्षित करने की उम्मीद है , जबकि दुनिया की ग्रामीण आबादी लगभग एक दशक में कम होने की संभावना है। शायद अधिक महत्वपूर्ण यह है कि लगभग सभी जनसंख्या वृद्धि विकासशील देशों के शहरों और कस्बों में होगी। यह इन क्षेत्रों के जनसंख्या वितरण में काफी बदलाव लाएगा, जो वर्तमान में शहरी केंद्रों में औसतन 40 और 48 प्रतिशत आबादी के साथ सबसे कम शहरीकृत हैं, बाकी दुनिया में लगभग 70-80 प्रतिशत (यूएनपीडी, 2014) के मुकाबले

सभी भूदृश्य गतिशील हैं और समय के साथ मानव और प्राकृतिक प्रक्रियाओं के संयोजन के कारण बदलते हैं। विशेष रूप से, दुनिया भर में सामाजिक संबंधों की हालिया प्रतिस्पर्धा में वैश्वीकरण ग्रामीण परिदृश्य को कई तरीकों से प्रभावित कर रहा है। प्रौद्योगिकी में बदलाव , बाजार, ग्रामीण-शहरी संबंध, वैश्विक और क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन और सरकार की नीति बदलते ग्रामीण परिदृश्य के मुख्य कारक हैं। कई अलग-अलग तरीकों से शहरीकरण भी ग्रामीण परिदृश्य परिवर्तन में योगदान दे रहा है और हाल के दशकों में इसका प्रभाव काफी बढ़ गया है। विश्व स्तर पर शहरी क्षेत्रों में रहने वाली एक महत्वपूर्ण शहरी आबादी देखी जाती है कि ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में अधिक लोग क्यों रहते हैं। अध्ययन क्षेत्र के अनुसार नैनीताल जिले के मौजूदा शहर में केंद्रीय बल है जो आसपास के क्षेत्रों को घेर रहा है। यह इंगित करता है कि घरों की संख्या के साथ-साथ प्रस्तावित नगर की धीरे-धीरे बढ़ती हुई जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी खेती योग्य भूमि को कम करने में परिवर्तन को दर्शाती है। भूमि की उच्च लागत के कारण लोगों ने इसके आसपास के उपनगरों को बसाना पसंद किया जो आर्थिक रूप से व्यवहार्य है और अन्य कारण जैसे पैनोरमा व्यू, सुविधाएं सुविधा। जो परिवर्तन हुए हैं वे सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन , बुनियादी ढांचे के विकास, परिवहन सुविधाओं, बैंकिंग, स्कूलों, स्वास्थ्य और पेशेवर संस्थानों आदि के उत्पाद हैं।



कृषि परिदृश्य का परिवर्तन

तेजी से शहरीकरण और तेजी से बढ़ती आबादी के दोहरे दबाव ने भारत में कृषि भूमि और भूमि प्रबंधन पर कहर बरपाया है। तेजी से शहरी विकास भूमि उपयोग पैटर्न बदलने की मानव समस्या है। तेजी से शहरीकरण सामान्य लक्षण बन जाता है जो दक्षिण और दक्षिणपूर्व एशिया के अधिकांश विकासशील देशों द्वारा अनुभव किया जाता है। भूमि स्थायी संपत्ति है और बढ़ती जनसंख्या वृद्धि के साथ बढ़ती नहीं है। जनसंख्या में वृद्धि और तेजी से हो रहे शहरीकरण के दबाव के कारण अन्य क्षेत्रों को आवश्यक भूमि से वंचित होना पड़ता है। कृषि भूमि मुख्य रूप से तेजी से शहरीकरण और इसकी मांग के कार्यों से प्रभावित होती है। आवासीय, उद्योग और वाणिज्यिक, नागरिक और संस्कृति के लिए भूमि उपयोग शहरी जगह में जगह के लिए बोली में कृषि भूमि का अधिग्रहण करते हैं। यह सर्वोच्चता कृषि योग्य भूमि के किसानों को खेती करने से वंचित करती है जिससे कृषि उत्पादकता कम हो जाती है। शहरी क्षेत्रों में, उत्तराधिकार और प्रभुत्व कारकों के बढ़ते प्रभाव ने किसानों के लिए भूमि को तेजी से कम कर दिया है। इनमें से एक भूमि उपयोग में परिवर्तन है जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश शहरी बस्तियों में आवासीय आवास के प्रावधान के पक्ष में कृषि भूमि में कमी आई है। Nsiah (2000) को ग्रामीण आबादी से शहरी आबादी में बदलाव के रूप में परिभाषित किया गया है और इसमें शहरी क्षेत्रों में लोगों की संख्या में वृद्धि शामिल है। चर्चा से एक बात स्पष्ट होती है कि एक विशेष नगरीय क्षेत्र में लोगों की सघनता है। इस प्रकार, शहरीकरण को एक समय में एक विशेष स्थान पर जनसंख्या के संचय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। शहरीकरण ने अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया था। यह माना जाता है कि मानव समाज और अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं को शामिल करने वाली परस्पर जुड़ी हुई घटना (विश्व बैंक, (2000)। शहरीकरण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास का परिणाम है जो शहरी एकाग्रता और बड़े शहरों के विकास की ओर ले जाता है, में परिवर्तन भूमि उपयोग और संगठन और सरकार के ग्रामीण से महानगरीय पैटर्न में परिवर्तन। नतीजतन, शहरीकरण ग्रामीण और शहरी सेटिंग दोनों में मानव जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। नई तकनीकों और व्यापक विकास ने वैश्विक स्तर पर कृषि उत्पादन में वृद्धि को सक्षम किया है। शहरीकरण ने भारी प्रभाव डाला है मिट्टी के कटाव, यूट्रोफिकेशन, जैव विविधता के नुकसान और जल संसाधनों के संदूषण के माध्यम से कृषि परिदृश्य की पारिस्थितिकी पर। शहरीकरण ने निस्संदेह



मानव जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है और खेती की भूमि को बदल दिया है और अध्ययन क्षेत्र में इसका कोई अपवाद नहीं है।

शहरीकरण का स्थानिक और अस्थायी परिप्रेक्ष्य: भविष्य का परिदृश्य

दुनिया भर में, शहरीकरण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है और महानगरीय क्षेत्र तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे व्यापक भूमि उपयोग परिवर्तन और शहरी स्थानिक विस्तार हो रहा है। 2005 के अनुमान में, कुल 3.2 बिलियन लोग शहरी निवासी थे, जो विश्व जनसंख्या का 48.7 प्रतिशत है (यूएनडीपी, 2005)। विकासशील देशों के शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि विशेष रूप से बढ़ रही है। तीव्र शहरीकरण का उत्पाद शहरी निर्मित क्षेत्रों द्वारा कृषि भूमि की खपत है। हालांकि औद्योगिक देशों में शहरीकरण की दर तेजी से नहीं बढ़ रही है, जहां 75 प्रतिशत आबादी शहरीकृत हो चुकी है, महानगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या की एकाग्रता लगातार बढ़ने की उम्मीद है (यूएनडीपी, 2004)। इसके अलावा, महानगरीय जनसंख्या परिधीय केंद्रीय शहर कई विकसित क्षेत्रों में डाउनटाउन क्षेत्रों की तुलना में तेजी से बढ़े हैं, जो शहरी क्षेत्रों के बाहरी विस्तार की एक मजबूत प्रवृत्ति का संकेत देते हैं। वास्तव में, कई शहर तेजी से अपने बाहरी किनारे पर बढ़ रहे हैं, गांवों और खेतों को घेर रहे हैं और उन्हें घने औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों, या कम घने उपनगरीय विकास में बदल रहे हैं। शहरी विस्तार को ग्रामीण क्षेत्रों से परिवर्तित विकसित और आवासीय क्षेत्रों में वृद्धि के रूप में देखा जाता है। मध्यम रूप से, शहरी विस्तार के कारण और परिणाम विवादास्पद क्षेत्र बने हुए हैं। जबकि शहरी विस्तार सामाजिक और आर्थिक विकास की प्रतिक्रिया में अपरिहार्य है और अक्सर इसे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन शक्ति के संकेत के रूप में देखा जाता है।

आज विश्व स्तर पर, शहरीकरण एक पर्यावरणीय समस्या बन गया है। शहरीकृत भूमि का पर्याप्त वितरण और कवरेज और जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण की गुणवत्ता पर शहरीकरण का प्रभाव इन दिनों विभिन्न अनुसंधान क्षेत्रों के विद्वानों द्वारा बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। यह व्यापक रूप से स्वीकृत सत्य है कि भू-दृश्य का स्थानिक पैटर्न सीधे पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। उसी समय स्थानीय या दूर के स्थानों से शहरी क्षेत्र में लोगों की आमद शहर की गतिशीलता और आकारिकी को बदल देती है और उत्पादक भूमि और साथ ही मानव और प्राकृतिक संसाधनों को ट्रिगर करती है। शहरी भूमि उपयोग योजना और प्रबंधन के साथ-साथ सतत विकास से संबंधित नए विकसित और अभिनव



दृष्टिकोण प्रस्तावित और चर्चा किए गए हैं। रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म द्वारा प्रदान की गई स्थानिक और लौकिक जानकारी को व्यापक रूप से लागू किया जाता है और स्थानिक प्रक्रियाओं की विशेषताओं को समझने और विकसित करने के लिए उपयोग किया जाता है।

भारत में शहरीकरण की बुनियादी विशेषताएं

भारत में शहरीकरण का स्वरूप बड़े शहरों में जनसंख्या और गतिविधियों की निरंतर एकाग्रता की विशेषता है। किंग्सले डेविस ने "अति-शहरीकरण" शब्द का इस्तेमाल किया, जहां शहरी दुख और ग्रामीण गरीबी साथ-साथ मौजूद हैं (किंग्सले डेविस और गोल्डन, 1954)। ब्रीज नाम के एक अन्य विद्वान ने भारत में शहरीकरण को छद्म शहरीकरण के रूप में दर्शाया है, जिसमें लोग शहरी खिंचाव के कारण नहीं बल्कि ग्रामीण धक्का कारकों के कारण शहरों में पहुंचते हैं (ब्रेसी, 1969)। रेजान कुंडू ने बेकार शहरीकरण और शहरी अभिवृद्धि की बात की, जिसके परिणामस्वरूप कुछ बड़े शहरों में जनसंख्या का संकेन्द्रण उनके आर्थिक आधार में समान वृद्धि के बिना होता है। शहरीकरण की प्रक्रिया मुख्य रूप से "प्रवास प्रेरित" नहीं है बल्कि प्राकृतिक विकास के कारण जनसांख्यिकीय विस्फोट का उत्पाद है। इसके अलावा, ग्रामीण आउट-माइग्रेशन कक्षा। शहरों (प्रेमी, 1991) की ओर निर्देशित है। बड़े शहरों ने असाधारण रूप से बड़ी आबादी का आकार हासिल कर लिया, जिससे शहरी सेवाओं और जीवन की गुणवत्ता में वस्तुतः पतन हो गया। अपर्याप्त आर्थिक आधार के कारण बड़े शहर कार्यात्मक इकाई होने के बजाय संरचनात्मक रूप से कमजोर और औपचारिक हैं। भारत में शहरी आबादी 1901 में लगभग 11 प्रतिशत से धीरे-धीरे बढ़कर 1951 में 17 प्रतिशत और फिर 2001 में 28 प्रतिशत हो गई। 1941-51 के दौरान शहरी विकास दर काफी अधिक 3.5 प्रतिशत प्रति वर्ष थी, लेकिन फिर घटकर कम हो गई। अगले दशक में 2.3 प्रतिशत। यह इंगित किया गया है कि 1940 के दशक का आंकड़ा उच्च पक्ष पर था, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद की गई पहली जनगणना में शहरी केंद्र की परिभाषा को मानकीकृत नहीं किया जा सका था और इसलिए भी कि देश के विभाजन के कारण बड़े पैमाने पर ग्रामीण-शहरी प्रवास हुआ था। शहरी विकास की उच्चतम दर (3.8 प्रतिशत) 1970 के दशक के दौरान दर्ज की गई थी, लेकिन बाद में 1980 के दशक में घटकर 3.1 प्रतिशत और 1990 के दशक में 2.7 प्रतिशत हो गई। इसकी कुछ अनूठी विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं: -

Ø एकतरफा शहरीकरण प्रथम श्रेणी के शहरों के विकास को प्रेरित करता है।

Ø शहरीकरण औद्योगीकरण और मजबूत आर्थिक आधार के बिना होता है।

Ø शहरीकरण मुख्य रूप से जनसांख्यिकीय विस्फोट और गरीबी से प्रेरित ग्रामीण-शहरी प्रवासन का एक उत्पाद है।

Ø तेजी से शहरीकरण से झुग्गी-झोपड़ियों में भारी वृद्धि होती है , जिसके बाद गरीबी, बेरोजगारी, शोषण, असमानताएं, शहरी जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आती है।

Ø शहरीकरण शहरी खिंचाव के कारण नहीं बल्कि ग्रामीण धक्का कारकों के कारण होता है।

Ø ग्रामीण-शहरी प्रवासन की खराब गुणवत्ता शहरीकरण की खराब गुणवत्ता की ओर ले जाती है (भगत , 1992)।

Ø आपदा प्रवासन शहरी क्षय की शुरुआत करता है।

शहरीकरण और ग्रामीण विकास

शहरीकरण का अर्थ है शहरों की संख्या और आकार में वृद्धि और शहरों में जीवन की गुणवत्ता का प्रसार। स्वाभाविक रूप से दुनिया के कई हिस्सों में वृद्धि और विकास अलग-अलग है। दूसरी ओर शहरीकरण का प्रभाव केवल कस्बों पर ही नहीं है। इसका असर ग्रामीण क्षेत्र पर भी पड़ा है। कई परिचारक घटनाएं शहरीकरण (आर्थिक विकास , ग्रामीण विकास , ढांचागत विकास आदि) से संबंधित हैं। प्राथमिक लक्ष्य शहरीकरण और ग्रामीण विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करना है।

शहरीकरण क्षेत्रीय विकास के साथ घनिष्ठ संबंध है। क्षेत्रीय विकास में पूरे देश का जुड़ाव और विकास , देश के विभिन्न क्षेत्रों और प्राकृतिक संसाधनों, जनसंख्या, उत्पादन और बुनियादी ढांचे की स्थिति के दृष्टिकोण से प्रत्येक बस्ती शामिल है। इस अवधारणा में क्षेत्रीय भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। अन्य लेखकों के अनुसार क्षेत्रीय विकास अन्य महत्वपूर्ण मानदंड दर्शाता है। फरागो (1992) के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र विशेष है ; इसलिए क्षेत्रीय विकास की कोई वैश्विक व्याख्या नहीं है और कोई सामान्य सार्वभौमिक क्षेत्रीय विकास दिशा नहीं है। नतीजतन हम केवल वैकल्पिक प्रवृत्तियों के बारे में बात कर सकते हैं।



विकास और विकास समान नहीं हैं। विकास का अर्थ मूल्यों के साथ परिवर्तन है जबकि विकास दरों में परिवर्तन दर्शाता है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विकास के साथ विकास जरूरी नहीं है। इसके अतिरिक्त विकास में बहुत सारे मूल्य हैं, जो हाल के आर्थिक, राजनीतिक, वैचारिक संबंधों से प्रभावित हैं। उदाहरण के लिए विकासशील देशों के मामले में हम अक्सर तेज आर्थिक विकास (नए हवाई अड्डे के निर्माण की परियोजना, शॉपिंग सेंटर निवेश आदि) का अनुभव कर सकते हैं, जबकि समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा इन विकासों से बाहर है। यह बिना विकास के विकास है।

सतत विकास विकास का एक प्रकार है। एक सामान्य नियम के रूप में सतत विकास का आधार, कि हाल की आर्थिक और सामाजिक जरूरतों की संतुष्टि भविष्य की जरूरतों की संतुष्टि को सीमित नहीं करती है। यह एक मौलिक सिद्धांत है। यह ज्ञात है कि विकास-उन्मुख आर्थिक और सामाजिक प्रक्रियाएँ इस सिद्धांत के उद्भव को प्रतिबंधित करती हैं। कई बिंदुओं पर यह सतत विकास के साथ असंगत है। शहरीकरण इस समस्या का एक हिस्सा है। आजकल अधिकांश जनसंख्या (6.2 मिलियन लोग) शहरों (3.2 मिलियन लोग) में रहती है। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में परिवर्तन किया गया है। नतीजतन, इस स्थिति ने कई सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक संघर्ष पैदा किए। शहरीकरण की दिशा न तो विकसित और न ही विकासशील देशों में बनाए रखी जाएगी।

शहरीकरण और क्षेत्रीय विकास

श्रम शक्ति औद्योगिक उत्पादन के स्थानिक विस्तार और उद्योग के विकास के साथ महत्वपूर्ण रूप से केंद्रित है। यही नगरीय-विस्फोट की विशेषता है। कस्बों और गैर-नागरिक बस्तियों की आबादी बढ़ रही है। शहरीकरण का यह दौर सबसे विकसित औद्योगिक देशों में लंबे समय तक चला। यह घटना 17वीं शताब्दी में शुरू हुई और सदियों तक चली। यह स्थिति तकनीकी सुधार के साथ थी। इस विकास का परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे खेतिहर मजदूर मेहनती बन गए। कुछ लोगों को ग्रामीण क्षेत्र से कस्बों, या उसके उपनगरों में हटा दिया गया। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों की जनसांख्यिकीय स्थिति को बदल दिया गया था।

वर्ष 1875-1900 के बीच शिकागो में शहरी-विस्फोट काल में विस्फोट की स्थिति को प्रदर्शित करता है। शिकागो उस समय सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर था। (बढ़ती दर 6% प्रति वर्ष थी)। उस दौरान



वहां की जनसंख्या में 1.3 मिलियन लोगों की वृद्धि हुई थी। जनसंख्या के एक सौ साल बाद 1975-2000 के बीच कुछ 10 मिलियन लोगों के साथ लागोस की जनसंख्या में वृद्धि हुई। इस मामले में बढ़ती दर 5 , प्रति वर्ष 8% थी. विकसित और विकासशील देशों में समान शहरी-विस्फोट की स्थिति का अनुभव नहीं किया जा सकता है। नगरीय-विस्फोट की निधियों का विकसित देशों में औद्योगिक विकास से घनिष्ठ संबंध है। इस देश में जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में चले गए , उनकी आजीविका और उनकी जनसांख्यिकीय , व्यवहारिक आदत बदल गई है। इसके विपरीत यह स्थिति विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में बाद में शहरी-विस्फोट शुरू हुई है। शहरी-विस्फोट विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों की अधिक आबादी के साथ घनिष्ठ संबंध है। यहां औद्योगिक विकास बहुत धीमा है: कस्बे उन लोगों का समर्थन नहीं कर सकते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से कस्बों में चले गए। इसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी दर में वृद्धि हुई है , और शहरी समाज के बड़े हिस्से को गरीबी से अलग होने का कोई मौका नहीं मिला है। इन देशों में जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में चले गए हैं , वे अपनी जनसांख्यिकीय और व्यवहार संबंधी आदतों को नहीं बदलते हैं।

निष्कर्ष

शहरी विस्तार ने विशेष रूप से परिवहन नेटवर्क के साथ-साथ भूमि के एक महत्वपूर्ण हिस्से का दावा किया। बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए व्यक्तिगत घरों और आवासीय कॉलोनियों दोनों को शहरी क्षेत्रों में देखा जाता है। वे वाणिज्यिक और औद्योगिक जेब के साथ शामिल हैं। किनारे की उपजाऊ कृषि भूमि को बिना खेती के छोड़ दिया जा रहा है , जिसका उपयोग किसी भी गतिविधि के लिए नहीं किया जा रहा है , निकट भविष्य में उच्च कीमतों का अनुमान लगाया जा रहा है। शहरी सीमाओं के साथ सट्टा भूमि का लगातार बढ़ता हिस्सा और अनियंत्रित शहरी विस्तार योजनाबद्ध शहरी विकास के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। उल्लेखनीय कृषि भूमि भी औद्योगिक उपयोग में परिवर्तित हो गई थी। यह एक अलग भूमि परिवर्तन पैटर्न का खुलासा करता है , जिसमें प्रारंभिक वर्षों में आवासीय भूमि उपयोग में मुख्य रूप से कृषि भूमि से भूमि लेने में काफी वृद्धि हुई है। यह जनसंख्या में वृद्धि और आवासीय स्थान की मांग का परिणाम था। लेकिन बाद के वर्षों में , वाणिज्यिक, औद्योगिक और सबसे महत्वपूर्ण रूप से खाली भूमि में प्रमुखता से वृद्धि हुई, जिनमें से अधिकांश रूपांतरित कृषि भूमि हैं। इसलिए , आसपास के शहर में भूमि परिवर्तन विशिष्ट भूमि परिवर्तन पैटर्न प्रदर्शित करता है जहां भूमि का परिवर्तन कई चरणों में होता है।



किनारे पर कृषि भूमि को सबसे पहले छोड़ दिया जाता है और खाली भूमि में परिवर्तित कर दिया जाता है। खाली पड़ी भूमि को बाद के चरण में आवासीय या अन्य शहरी भूमि उपयोग के लिए विकसित किया जाता है।

संदर्भग्रंथ सूची

- सहगल, के.के. (2017) मध्य प्रदेश में कृषि विकास पर शहरीकरण का प्रभाव। इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, 27, 77-85।
- वत्स, पी.सी. (2017) इंप्लुएंस् ऑफ माइक्रो-जियोमॉर्फोलॉजिकल यूनिट्स ऑन लैंडयूज एंड क्रॉप प्रोडक्शन - ए केस स्टडी ऑफ विलेज डंडली , राजस्थान। डेक्कन जियोग्राफर्स, 15, नंबर 2, 317 - 323।
- जयकुमार, एस. और डी.आई. अरोकिसामी (2017) लैंड यूज/लैंड कवर मैपिंग एंड चेंज डिटेक्शन इन द पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स ऑफ तमिलनाडु। जर्नल ऑफ़ द इंडियन सोसाइटी ऑफ़ रिमोट सेंसिंग , 31, संख्या 4, 251-260।
- वर्मा एल.एन. (2016) शहरी भूगोल पृष्ठ.172, रावत प्रकाशन, नई दिल्ली।
- वानवमबेके, एस.ओ., पी. सोम्बून, और ई. लेम्बिन (2017) उत्तरी थाईलैंड में ग्रामीण परिवर्तन और भूमि उपयोग परिवर्तन। जर्नल ऑफ लैंड यूज साइंस, 2, नंबर 1, 1-29।
- वेलमुरुगन, टी., पी. नारायण, जी. सिंह (2019) लैंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन इन देहरादून जिला, उत्तराखंड। डेक्कन भूगोलवेत्ता, 48।
- प्रायर, आर.जे. (2018)। ग्रामीण-शहरी फ्रिज की परिभाषा , सामाजिक बल, वॉल्यूम। 47, पीपी. 202-215.
- रामचंद्र, टी.वी., ऐथल, बी.एच., और सौम्यश्री, एम.वी. (2019)। अहमदाबाद शहर , भारत के कपड़ा केंद्र में शहरी गतिशीलता के स्थानिक पैटर्न की निगरानी। स्पैटियम इंटरनेशनल रिव्यू , 1(31), 85-91।
- ब्रायंट, सी.आर., रसवर्म, एल.एच. और मैकलीनन , ए.जी. (2017)। द सिटीज कंट्रीसाइड: लैंड एंड इट्स मैनेजमेंट इन द रूरल-अर्बन फ्रिज: एडिसन-वेस्ले लॉन्गमैन लिमिटेड, पीपी। 10-14।
- बेंटिक, जे. वी. (2020)। दिल्ली के हाशिये पर अनियंत्रित शहरीकरण। ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय।



- हेमलिच, आर.ई., और एंडरसन, डब्ल्यू.डी. (2021)। शहरी सीमा पर विकास और कृषि और ग्रामीण भूमि पर प्रभाव से परे।
- तिरुमूर्ति, ए.एम. (2017)। चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया, पेरीअर्बन प्रोजेक्ट रिपोर्ट में पेरी-अर्बन फॉर्मेशन की प्रक्रिया।
- नारायण, वी।, और निश्चल, एस। (2017)। शाहपुर खुर्द और करनारा, भारत में पेरी-अर्बन इंटरफ़ेस। पर्यावरण और शहरीकरण, 19(1), 261-273। <https://doi.org/10.1177/0956247807076905>
- तीव्र, जे.एस., और क्लार्क, जे.के. (2018)। देश और कंक्रीट के बीच: ग्रामीण-शहरी सीमा को फिर से खोजना। सिटी एंड कम्युनिटी, 7(1), 61-79। <https://doi.org/10.1111/j.1540-6040.2007.00241.x>
- फ़ज़ल एस (2020) दूरी के संबंध में शहरी भूमि परिवर्तन, एक केस स्टडी। इन: सिंह आरबी (एड) सतत शहरी विकास। कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली, पीपी 187-204
- साइमन (2020)। शहरी/उपनगरीय भूमि उपयोग विश्लेषण। आर. एन. कोलवेल में, एफ.टी. उलाबी, डी.एस. साइमनेट, जे.ई. एस्टेस, और, जी.ए. थॉर्ली (ईडीएस), मैनुअल ऑफ़ रिमोट सेंसिंग: इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन्स (वॉल्यूम 2) (पीपी. 1571-1666)। वर्जीनिया, यूएसए
- कर्मकार, जे। (2017)। कोलकाता के पेरी शहरी क्षेत्रों में नियोजन प्रक्रिया की वास्तविकता का सामना करना: राजारहाट का केस स्टडी। एप्लाइड साइंस रिसर्च के अभिलेखागार, 7(5), 129-138।